DSSSB TGT & PGT
Part-B
SCHOLAR BATCH
INDIAN ECONOMY
स्वयं सहायता समूह
LIVE
23-07-2024 08:00 PM

SHG Groups

स्वयं सहायता समूह

- स्वयं सहायता समूह ग्रामीण आधारित वित्तीय मध्यस्थता समूह है. जिसमें आमतौर पर 10 -200 तक स्थानीय महिलाएँ या पुरुष जुड़े होते है |
- पिछले कुछ वर्षो को देखा जाये तो महिलाओं ने इसमे काफी बढ़-चढ़कर भाग लिया है, जिससे समाज मे उनकी स्थिती मे सकारात्मक वदलाव देखने को मिले है

- स्वयं सहायता समूह के सदस्य अपने नियमित बचत में से एक कोश बना लेते है और और उस धन का उपयोग आपातकालीन स्थिती मे या अपने सामूहिक उद्देश्य के कार्य हेतू मे करते है।

- कोष के पैसो से ग्रामीण आधारित सूक्ष्म या लघु उद्योग की शुरुवातभी करते है जिस से रोजगार के अवसर सृजित होते है, उसके बाद होने वाले मुनाफे को बराबर आपस मे बाटते है।

- इस समूह मे से एक को नेतृत्व दे दिया जाता है, और वही फिर सारे प्रबंधन का कार्य करता है। समूह को बैंको से जोड दिया जाता है, जिससे वित्तीय लेन-देन मे आसानी होती है

स्वयं सहायता समूह के लक्ष्य

- सामाजिक व आर्थिक सुधार हेतू
- महिलाओं के अंदर विश्वास और नेतृत्व क्षमता को विकसित करना जिस से समाज मे लैंगिक भेदभाव को कम किया जा सके
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना

भारत मे खाद्य सुरक्षा

- खाद्य सुरक्षा का मतलब है लोगो के पास हमेशा भोजन उपलब्ध होना

खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम है,

- खाद्य की उपलब्धता (Available)
- खाद्य की पहुंच (Access)
- सामर्थ्य (Power)

खाद्य की उपलब्धता

- इसका आकलन इस बात से लगाया जाता है कि देश मे कुल उत्पादन कितना कितना हुआ, कितना खाद्य नियति हुआ और सरकारी भंडारो मे पिछले वर्षो का स्टॉक कितना है।

खाद्य की पहुँच

- इसका मतलब है कि खाद्य की पहुँच हर व्यक्ति तक है।

सामर्थ्य -

- इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा सुरक्षित और पोषक भोजन खरीदने के लिये पर्याप्त रुपये है।

खाद्य सुरक्षा की जरूरत

- खाद्य सुरक्षा की जरूरत कई उद्देश्यों के लिए होती है। सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी व्यक्ति को खाली पेट नहीं सोना पड़े। दूसरा उद्देश्य है कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में इतना अधिशेष खाद्य रहना चाहिए ताकि आपदा से प्रभावित लोगों को समुचित मात्रा में खाद्य की आपूर्ति हो सके।

अकाल

- जब भुखमरी के कारण या मजबूरी में दूषित जल पीने या सड़े हुए भोजन को खाने के कारण बड़े पैमाने पर लोगों की मौत होने लगे तो ऐसी स्थिति को अकाल कहते हैं। 1943 का बंगाल का अकाल इतिहास का सबसे भीषण अकाल था। इस अकाल में बंगाल में लगभग 30 लाख लोग मारे गये थे।

खाद्य असुरक्षा

खाद्य असुरक्षा से सबसे अधिक पीड़ित होने वाले लोग हैं भूमिहीन गरीब परंपरागत दस्तकार, परंपरागत सेवा प्रदान करने वाले छोटे-मोटे काम करने वाले और बेसहारा लोग। शहरी इलाकों में जो लोग कम मेहनताने वाले काम करते हैं और जो मौसमी काम करते हैं, वो खाद्य असुरक्षा की समस्या से ग्रसित होते हैं।

राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) और ओडिसा की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खाद्य असुरक्षा से पीड़ित हो सकता है।

भुखमरी न केवल गरीबी की निशानी होती है बल्कि यह गरीबी को लाती भी है। भुखमरी मौसमी या फिर दीर्घकालिक हो सकती है। जो लोग बहुत कम कमाते हैं और अधिकतर समय भुखमरी के शिकार रहते हैं उनमें दीर्घकालिक भुखमरी देखने को मिलती है। मौसमी भुखमरी अक्सर कृषि के चक्र से संबंधित होती है। कई भूमिहीन किसान और सीमांत किसान भी मौसमी भुखमरी के शिकार होते हैं। शहरी इलाकों में जिन लोगों को मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है उन्हें मौसमी भुखमरी से जूझना पड़ता है।

भारत में भुखमरी से पीड़ित परिवारों का प्रतिशत

वर्ष	भुखमरी का प्रकार		
	मौसमी	दीर्घकालिक	कुल
ग्रामीण 1983	16.2	2.3	18.5
1993-94	4.2	0.9	5.1
1999-2000	2.6	0.7	3.3
शहरी 1983	5.6	0.8	6.4
1993-94	1.1	0.5	1.6
1999-2000	0.6	0.3	0.9

इस टेबल से पता चलता है कि भारत में खाद्य असुरक्षा से ग्रसित लोगों का प्रतिशत काफी नीचे चला गया है, जो कि एक अच्छी बात है।

इन्वायरमेंट एण्ड इकोलॉजी

- PCS Batch
- Recorded class
- Live method
(क्लास में complete)
@ 9 pm

प्रथम पंचवर्षीय योजना
(1951-1956)

मुख्य उद्देश्य = खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त करना
↓
कृषि विकास
सिंचाई साधनों का विस्तार

- हीराकुड
- दामोदर
- भाखड़ा नांगल

हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)

कृषि → महाउद्योगों की स्थापना

प्रो पी सी महालनोबिस मॉडल

स्टील पावर प्लांट

राउरकेला

दुर्गापुर । भिलाई

तृतीय पंचवर्षीय योजना
(1961–66)

संयुक्त

कृषि उद्योग

दोनों पर संयुक्त रूप से ध्यान

1962 – इण्डो चाइना वार
1965 – इण्डो पाक वार
भीषण अकाल

→ × तीन एक-एक वर्षीय योजना

1966–67
67–68
68–69

पुनरावलोकन
समीक्षा
कुर्सियों
के नाम

(मुख्य लक्ष्य
कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता
हरितक्रांति
Green Revolution

हरितक्रांति

उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जायेगा।

आधुनिक सिंचाई पद्धति

उर्वरकों (रासायनिक)

कीटनाशक

कृषिविस्तार

(गेंहू, चावल) — पंजाब, हरियाणा, प० उ०प्र०

हरित क्रांति का प्रभाव

- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। 1970 के दशक में हरित क्रांति के शुरु होने से आज तक एक बार भी अकाल नहीं पड़ा है जबकि इस बीच कई वर्ष ऐसे बीते हैं जब मौसम प्रतिकूल था। खाध्यान्न का उत्पादन 1960-61 के 70 मिलियन टन से बढ़कर 2015-16 में 252 मिलियन टन हो गया। 2016-17 में 275 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ।

बफर स्टॉक

- भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा खरीदे गये खाधान्न (गेहूं और चावल) के स्टॉक को बफर स्टाक कहते है जिन राज्यो मे विशेष अधिशेष उत्पादन होता है, वहा से FCI गेंहू और चावल खरीदता है। इसके लिये समय- समय पर सरकार द्वारा MSP निर्धारित की जाती है। बफर स्टॉक के कुछ हिस्से को कम कीमत पर गरीबो को खाधान्न दिया जाता है। इस कीमत को निर्गत कीमत कहते है बाकी के बफर स्टॉक को सुरक्षित रखा जाता है, ताकि किसी आपदा मे काम आये।

बफर स्टॉक की स्थिति

- 2002 की जुलाई में एफसीआई के पास खाद्यान्न का 63 मिलियन टन स्टॉक था जो कि निर्धारित स्टॉक (23.4 मिलियन टन) से बहुत अधिक था जब 2002-03 में सुखा पड़ा था तो राहत देने के क्रम में एफसीआई का स्टॉक कुछ हद तक खाली हुआ। बफर स्टॉक का अधिक होना एक अच्छी बात है लेकिन इससे कई समस्याएँ भी उठ खड़ी हुई है। एफसीआई के गोदामों में अनाज या तो सड़ जाता है या फिर उन्हें चूहे खा जाते हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य से समस्या

- गेहूं और धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने से कई समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज बेचने के उद्देश्य से अधिकतर किसान अब गेहूँ और धान उगाने पर अधिक ध्यान देते हैं। इससे मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, मक्का) की कमी होने लगी है। धान और गेहूँ कि खेती में गहन सिंचाई की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण भोग जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है।

कई राज्यों में सहकारी समितियों ने पीडीएस से बेहतर काम किया है। तमिलनाडु में 94% राशन की दुकाने सहकारी समितियों द्वारा चलाई जा रही हैं। महाराष्ट्र में एकडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने अनाज बैंकों की स्थापना में गैर-सरकारी संगठनों की सहायता की है जिससे गरीबों को लाभ मिल रहा है। दिल्ली में मदर डेयरी की दुकानों के द्वारा लोगों तक फल सब्जियाँ और दूध सस्ते दरों पर पहुंचाया जा रहा है। गुजरात का अमूल दूध और दूध उत्पादों को घर घर पहुंचाने में सहकारी समिति का एक सफल उदाहरण है।

Thank you!

Thank you!